



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939

No. 205]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/ SRAVANA 18, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2017

अंतिम जाँच परिणाम

विषय : चीन जन. गण., के मूल की या वहां से निर्यातित 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन के आयातों से संबंधित
निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जाँच

सं. 15/3/2016 -डीजीएडी - समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. और जबकि, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 16 नवंबर, 2011 की अधिसूचना सं. 14/11/2004-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए थे जिनमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या

विचाराधीन उत्पाद या पइराजोलोन कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10 जनवरी, 2006 की अधिसूचना सं. 01/2006-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. और यतः प्राधिकारी ने दिनांक 1 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. 15/5/2010-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत के अनुपालन में दिनांक 29 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 15/5/2010-डीजीएडी द्वारा अंतिम जाँच परिणाम जारी किए जिनमें संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 80/2011-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क की समयावधि को बढ़ाया गया था।
3. यतः, मैं, प्राइमा कैमिकल्स और मैं, पालीगान कैमिकल्स द्वारा (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया गया है।
4. यतः प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 11 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 15/3/2016-डीजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरुआत की ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की आशंका है।
5. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमों के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने चीन जन. गण. से आयातों के विरुद्ध संबद्ध वस्तु पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समयावधि को दिनांक 19 अगस्त, 2016 की अधिसूचना सं. 47/2016 द्वारा 23 अगस्त, 2017 तक बढ़ा दिया है।

ख. प्रक्रिया

6. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - क. प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों और घरेलू उत्पादकों को दिनांक 11 अगस्त, 2016 की जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजीं। ज्ञात हितबद्ध पक्षों से विहित समय-सीमा के भीतर लिखित में प्रश्नावली का उत्तर देने और उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।
 - ख. निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची के साथ संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गईं तथा उनसे संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया।
 - ग. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुरूप आवेदक की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई थी।
 - घ. नियमावली के नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार प्राधिकारी ने संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस

दिनों के भीतर लिखित में उनके विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया:

मैं. गोल्डलिक इंडस्ट्रीज कं. लि.

17/एफ, 258, झांग सान रोड, वुक्सी, चीन

मै. जिआंगसू चांगयू कैमिकल कं. लि.

झोंगजिचांग लेयू टाउन झाजियांग सिटी

जिआंगसू, **215621**, चीन जन. गण.

मैं. किंडाओ बांगली फाइन कैमिकल कं. लि.

सं. **608** यानशान रोड ओइंगडाओ सिटी चीन

मैं. किंगडाओ डबल-पीच स्पेशियलिटी कै. (ग्रुप) कं. लि.

ब्लाक सी, **43**, झेंगझाउ रोड किंगडाओ चीन

मैं. वेनझाउ मायरनू कैमिकल कं. लि.

संपर्क : झेजियांग वेनझाउ ओहाइ किकिआओ स्ट्रीट निंगबो रोड जिप कोड:

325000, चीन

मैं. जिनान जियांगु कैमिकल कं. लि.

सं. **12406**, जिंगशी रोड, जिनान, शानडांग, चीन

मैं. शानडोंग जिनहुआ फार्मास्युटीकल कं. लि.

जिबो, शानडोंग, चीन

मैं. शोगुआंग नुआमिंग कैमिकल कं. लि.

हुझेन इंडस्ट्रीयल पार्क, शुगुआंग, शानडांग, चीन

ड. संबद्ध जाँच की शुरुआत के उत्तर में संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर देकर और अनुरोध करके उत्तर नहीं दिया है।

च. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गईं:

मैं. एपेक्स डाइज एंड इंटरमीडिएट्स

आफिस अजंता कमर्शियल सेंटर

आश्रम रोड, अहमदाबाद **380014**

मैं. एएस एसोसिएट्स ड्रग कं.

27 बुल टेंपल रोड, बंगलोर

मैं. पीडिलाइट इंडस्ट्रीज लि.

रामकृष्ण मंदिर रोड

कार्या. एम. वासनजी रोड

अंधेरी पूर्व, मुंबई 400059

मैं. एशियाटिक कलर्स कैम इंड लि.

प्लॉट सं. 1503, 04 जी.आई.डी.सी. इस्टेट

फेस-1, नरोदा, अहमदाबाद

मैं. अंकुर डाइस्टफ इंडस्ट्रीज,

39, जी.एल.डी.सी., फेस एल1

वातवा, अहमदाबाद

मैं. जानसंस इंटरनेशनल

101, जाली भवन सं. 1

10, न्यू मरीन लाइंस, मुंबई-400 200

मैं. के रसिकलाल एंड कं.

आर सं. 5, लिंड फ्लोर, 339/340, सैमुअल स्ट्रीट

मस्जिद मुंबई 3

मैं. नीलकंठ कैमिकल्स,

प्लॉट सं. 8021, जीआईडीसी इस्टेट, सचीने, सूरत

- छ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और न ही अनुरोध किया है।
- ज. ऐसे निर्यातक, विदेशी उत्पादक और अन्य हितबद्ध पक्ष जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत की है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्ष माना गया है।
- झ. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और अपेक्षित विश्लेषण की गणना के लिए डीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- ञ. सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की ईष्टतम लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत को ज्ञात किया गया है इस बात का पता लगाया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित

सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

- ट. यह जांच (पीओआई) अप्रैल 2015 से शुरू होकर मार्च 2016 (जांच अवधि) तक की अवधि के लिए की गई थी। तथापि, क्षति जाँच में अप्रैल 12 - मार्च 13, अप्रैल 13 - मार्च 14, अप्रैल 14 - मार्च 15 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल है।
- ठ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 10 जुलाई, 2017 को आयोजित आम सुनवाई में अपना दृष्टिकोण मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिया। केवल घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया और मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया।
- ड. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करावें।
- ढ. जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अंतिम जाँच परिणामों को दर्ज किया है।
- ण. नियमावली अनुसार प्राधिकारी ने 22 जुलाई, 2017 को मामले के अनिवार्य तथ्यों के प्रकटन वाले प्रकटन विवरण को हितबद्ध पक्षों की टिप्पणियों के लिए जारी किया था। प्रकटन विवरण के संबंध में केवल घरेलू उद्योग ने टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। टिप्पणियों के संगत होने की सीमा तक उनका समुचित स्थानों पर इस जाँच परिणाम में समाधान किया गया है।
- त. *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।
- थ. पीओआई के दौरान विद्यमान औसत विनियम दर इस प्राधिकारी द्वारा 1 अमरीकी डॉलर = 65.91 रुपया लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु

घरेलू उद्योग के अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- क. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन है, जिसे पाइरोजोलोन भी कहा जाता है।
- ख. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा मूल जाँच और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में परिभाषित किया गया है।
- ग. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित पाइरोजोलोन और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित पाइरोजोलोन भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के अनुसार तुलनीय है और उपभोक्ता इनका प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं और कर रहे हैं।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पाइरोजोलोन और संबद्ध देश से आयातित पाइरोजोलोन को पाटनरोधी नियमावली के अनुसार समान वस्तु माना जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

9. मूल जाँच, पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा और वर्तमान जाँच में भी विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन है। मूल जाँच और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :

"10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जैसा मूल जाँच में परिभाषित किया गया है। पूर्ववर्ती और वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन है जो एक कार्बनिक रसायन है जिसे अध्याय 29 के अधीन उपशीर्ष सं. 2933 19 20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग एनलजिन, विलायक डाइ और पिगमेंट डाइ और पिगमेंट आरेंज 13 के विनिर्माण के लिए रंजक और भेषज उद्योग में किया जाता है। संबद्ध वस्तु के आयातों की सीमाशुल्क वर्गीकरण सं. 293319, 291634, 291739, 292429, 293311, 293359, 294200, 980200 के अधीन भी होने की सूचना मिली है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। प्राधिकारी द्वारा जाँच के अधीन विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। इसके अलावा, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से किसी उत्तर के अभाव में घरेलू उद्योग और प्राधिकारी के मत के विपरीत कोई विचार नहीं है। अंतः प्राधिकारी का यह प्रस्ताव है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के भीतर ये दोनों समान वस्तु हैं।"

10. चूंकि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और प्राधिकारी द्वारा पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू है इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल और मध्यावधि समीक्षा जाँच के समान ही रहेगा। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने समीक्षा के दायरे में संशोधन (कटौती करने सहित) का अनुरोध करते हुए कोई बात नहीं की है।

11. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु भारत में आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के समान है। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग के उत्पाद और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है और ये दोनों भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु के बीच कोई खास अंतर नहीं है और ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

12. प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। यह भी नोट किया जाता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जाँच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे की जाँच की है जिस पर भरोसा किया गया है। नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु को समान वस्तु माना गया है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के अर्थ और दायरे के अनुसार समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

13. घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरे के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. मैं. वाणी फार्मा लैब्स और मैं. कलरजेट कैमिकल्स प्रा लि. आवेदकों के अलावा उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के केवल अन्य ज्ञात उत्पादक हैं।

ख. इन उत्पादकों का उत्पादन उपलब्ध नहीं है। किसी भी तरह से आवेदकों का उत्पाद आसानी से कुल भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक रहेगा।

ग. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक/उत्पादक या आयातक से संबंधित नहीं हैं और न ही उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैं. प्राइमा कैमिकल्स और मैं. पालीगान कैमिकल्स द्वारा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध करने वाला आवेदन दायर किया गया था। मूल जाँच और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जाँच के अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी ने मैं. प्राइमा कैमिकल्स और मैं. पालीगान कैमिकल्स को पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2 (ख) की जरूरतों के अनुसार घरेलू उद्योग माना था। याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि मैं. वाणी फार्मा लैब्स और मैं. कलरजेट कैमिकल्स प्रा लि. ने अपनी वेबसाइट पर संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने का दावा किया है परंतु उन्होंने इस जाँच और पूर्व जाँचों में उत्तर नहीं दिया है। रिकार्ड की सूचना के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनियों का उत्पादन पीओआई के दौरान भारतीय उत्पादन का *** हिस्सा बनता है। संबद्ध वस्तु संबंधी पूर्ववर्ती जाँच और प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि मैं. प्राइमा कैमिकल्स और मैं. पालीगान कैमिकल्स हर तरह से कुल भारतीय उत्पाद का "प्रमुख हिस्सा" बनते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे उसके किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं।

16. प्राधिकारी को यह बताया गया है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से पालीगान कैमिकल्स का प्राइमा कैमिकल्स में विलय हो गया। तथापि यह नोट किया जाता है कि यह घटना जाँच अवधि के बाद हुई है और इसके अलावा चूंकि यह विलय एक आवेदक कंपनी का दूसरी कंपनी में है इसलिए आवेदकों को वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ अलग परंतु संबंधित कंपनियां माना गया है।

17. उक्त स्थिति को देखते हुए और नियमावली और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि मैं. प्राइमा कैमिकल्स और मैं. पालीगान कैमिकल्स वर्तमान समीक्षा जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग हैं।

ड. पाटन मार्जिन का निर्धारण**बाजार अर्थव्यवस्था दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन****घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

18. बाजार अर्थव्यवस्था दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :

- क. चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 (ख) का अर्थ है कि खंड 15(क)(ii) के उपबंध चीन के एक्सेसन की तारीख से 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे अर्थात् इस पैराग्राफ के उपबंध 15 वर्षों अर्थात् दिसंबर 2016 तक उपलब्ध रहेंगे। इसका अर्थ है कि प्राधिकारी को लागत और सामान्य मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया पर विचार करना होगा।
- ख. इस संबंध में संगत विचार जाँच अवधि का ही होना चाहिए क्योंकि जाँच अवधि के निर्धारण का प्रयोजन उस अवधि पर विचार करना था जब पाटन की मौजूदगी से क्षति होना सिद्ध हुआ हो और यह कि पीओआई के बाद की घटनाएं निर्धारण के लिए संगत नहीं हैं।
- ग. चूंकि वर्तमान मामले में पीओआई अप्रैल 2015 - मार्च, 2016 (12 महीने) है, इसलिए अनुच्छेद 15 के उपबंध वर्तमान जाँच अवधि पर पूर्णतः लागू होंगे। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा - 7 के आधार पर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से नियमावली के पैरा 7 और 8 के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करेंगे। पैरा 7 और 8 के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से पहले प्रस्तुत याचिका के साथ संलग्न विस्तृत अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया है।
- घ. चीन में सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को विधिवत रूप से समायोजित करके और याचिकाकर्ता के खपत मानकों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है।
- ङ. याचिकाकर्ता ने आईबीआईएस द्वारा प्रदत्त आयात आकड़ों पर भरोसा किया है। आयात आकड़ों में सूचित मूल्य सीआईएफ मूल्य है। निर्यात कीमत सीआईएफ मूल्य है जबकि सामान्य मूल्य कारखाना द्वार स्तर पर हैं इसलिए निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों पर हुए व्यय के लिए समायोजित किया गया है।
- च. चर्चा के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने पाटन मार्जिन निर्धारित किया है, जिसका ब्योरा रिकार्ड में याचिका से देखा जा सकता है। संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक हैं बल्कि पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के बावजूद काफी अधिक हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

19. चूंकि किसी हितबद्ध पक्ष ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए बाजार अर्थव्यवस्था दावे, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य

20. चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है :

गैट 1994 का अनुच्छेद 4, टैरिफों और व्यापार हेतु सामान्य करार 1994 के अनुच्छेद 4 के कार्यान्वयन संबंधी करार (पाटनरोधी करार) और एससीएम करार चीन के डब्लूटीओ के सदस्य के रूप में आयात शामिल करने की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित से संगत होने पर लागू होंगे:

(क) गैट 1994 का अनुच्छेद 4 और पाटनरोधी करार के अधीन कीमत तुलनीयता निर्धारित करने के लिए आयातक डब्लूटीओ देश या तो चीन की कीमतों या जाँच के अधीन उद्योग की लागतों या ऐसी पद्धति का प्रयोग करेगा जो निम्नलिखित नियम के अधीन घरेलू कीमतों और चीन में लागतों की कड़ी तुलना पर आधारित हों:

- (i) यदि जाँच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकते हों कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं, तो आयातक डब्लूटीओ सदस्य कीमत तुलनीयता के निर्धारण के लिए जाँच के अधीन उद्योग हेतु चीन की कीमतों या लागतों का प्रयोग करेगा।*

(iii) आयातक डब्लूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का इस्तेमाल कर सकता है जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो परंतु यदि जाँच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकता हो कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पादन उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं।

(ख) एससीएम करार के भाग II, III और V के अधीन कार्यवाही में, जब एससीएम करार के संगत उपबंधों के अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14 (घ) में वर्णित सब्सिडी पर विचार करना लागू हो : तथापि यदि उस अनुप्रयोग में विशेष कठिनाई हो, तो आयातक डब्लूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान और माप के लिए ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जिसमें इस संभावना पर विचार हो कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें हमेशा समुचित बेंचमार्कों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों के प्रयोग में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्लूटीओ सदस्य को चीन से बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्लूटीओ सदस्य पाटनरोधी प्रथाओं संबंधी समिति के उप पैराग्राफ (क) के अनुसार पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति के उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार आयातक डब्लूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अधीन चीन के बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश सिद्ध होने पर, उप पैराग्राफ (क) के उपबंध समाप्त हो जाएंगे परंतु यह कि आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में शामिल होने की तारीख को बाजार अर्थव्यवस्था के मापदंड शामिल हों। किसी स्थिति में उपपैराग्राफ (क)-(ii) के उपबंध शामिल होने की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा क्या चीन को आयातक डब्लूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार यह सिद्ध करना होगा कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं उस उद्योग या क्षेत्र विशेष में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के उपबंध उस उद्योग या क्षेत्र पर अब लागू नहीं होते हैं?"

21. अनुच्छेद 15 का अर्थ है कि एक उप पैराग्राफ के उपबंध चीन के शामिल होने की तारीख से 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस पैराग्राफ के उपबंध 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि पाटन के घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का तथ्य जाँच अवधि के आधार पर सिद्ध हो गया है इसलिए जाँच अवधि के दौरान प्रचलित स्थिति ही संगत समुचित है और वर्तमान जाँच के लिए आवश्यक है। वर्तमान समीक्षा के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2015 से मार्च 2016 है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप पैराग्राफ जाँच की अवधि के दौरान मौजूद था प्राधिकारी ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं जो घरेलू कीमतों या चीन में लागत की कड़ी तुलना पर आधारित न हो यदि जाँच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाते हों कि उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं प्रचलित हैं।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में चीन जन. गण. को भारत और अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा पाटनरोधी जाँचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा इस धारणा के खंडन के अधीन माना गया है।

प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था के दावे की जाँच

23. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मापदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने के लिए **संबद्ध देश के** सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की

प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी उनके देश में उत्पादकों/निर्यातकों को अपेक्षित सूचना देने की सलाह देने के लिए कहने का अनुरोध किया। यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के पैराग्राफ 8, अनुबंध 1 के अनुसार, गैर बाजार अर्थव्यवस्था की धारण का खंडन किया जा सकता है यदि निर्यातक पैराग्राफ 8 में उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराएं और इसके विपरीत सिद्ध करें। तथापि, संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है और वर्तमान जाँच में निर्यातक प्रश्नावली और एमईटी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस स्थिति में और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा के खंडन के अभाव में प्राधिकारी चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार कार्रवाई करना उचित समझते हैं।

च. सामान्य मूल्य का निर्धारण

24. संबद्ध देश से किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है और वर्तमान जाँच में उत्तर नहीं दिया है। इसके अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने नियमों में यथा परिभाषित ऐसा कोई वैकल्पिक आधार नहीं बताया है जिस पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सके।

25. उक्त स्थिति को देखते हुए और चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानते हुए, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में यथा शामिल अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने 'अन्य तर्कसंगत आधार' पद्धति को अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य प्रमुख कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और कच्ची सामग्री की सर्वोत्तम खपत मानकों को अपनाकर परिकलित किया है। लागत के अन्य तत्व सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक की ईष्टतम लागत पर आधारित हैं। बिक्री की परिकलित लागत पर वित्त लागत घटाकर 5 प्रतिशत के लाभ मार्जिन की अनुमति दी गई है। तदनुसार, चीन जन.गण. के निर्यातकों के लिए परिकलित सामान्य मूल्य नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार *** अम.डा. प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।

छ. निर्यात कीमत

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने विहित ढंग और तरीके से प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। पूर्वोक्त देशों से उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर इन देशों के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित की है। प्राधिकारी ने पीओआई के दौरान पूर्वोक्त देशों से आयातों के भारित औसत सीआईएफ मूल्य को ज्ञात करने के लिए डीजीसीआईएंडएस आयात आकड़ों पर भरोसा किया है। उक्त देशों के लिए निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैंक प्रभारों के अनुसार समायोजन पर विचार किया गया है। तदनुसार, चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों के लिए कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका के अनुसार निर्धारित की गई है।

ज. पाटन मार्जिन

27. पूर्वोक्त यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यातक कीमत की तुलना करने पर पीओआई के दौरान संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :

जाँच अवधि (2015-16)

देश	निर्यातक/ उत्पादक	सामान्य मूल्य अम.डा./कि ग्रा.	निवल निर्यात कीमत अम.डा./किग्रा.	पाटन मार्जिन अम.डा./किग्रा .	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
चीन जन. गण	कोई भी	***	***	***	***	5-15

28. उक्त तालिका से पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन जारी रहा है।

झ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति और कारणात्मक संबंध की जाँच**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

29. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयातों से अब भी घरेलू उद्योग की कटौती जारी है और वह भी काफी अधिक मार्जिन से जो वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की दशा में इसमें आगे और वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।
- ख. उत्पादन लागत और बिक्री कीमत की तुलना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में पूरी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से काफी अधिक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयातों से घरेलू बाजार में घरेलू कीमतों में गिरावट आ रही है।
- ग. घरेलू उद्योग की क्षमता भारतीय मांग से तुलनीय है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का आसानी से उपयोग कर सकता था और घरेलू बाजार में आयात आवश्यक नहीं हैं।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में उस अवधि के दौरान लागू पाटनरोधी शुल्क के स्वाभाविक परिणामस्वरूप वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है। तथापि, वह प्राप्य स्तर से काफी कम रहा है।
- ड. घरेलू उद्योग की मालसूची में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- च. लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और नकद लाभ पूरी क्षति में सभी प्रतिकूल रहे हैं। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है। घाटों में कमी हुई है तथापि वे अधिक बने हुए हैं। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय में मामूली सुधार हुआ है।
- छ. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता के बावजूद संबद्ध आयातों का भारी बाजार हिस्सा है।
- ज. उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए क्षति अवधि में उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को अब भी देश में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण वित्तीय घाटा उठाना पड़ रहा है।
- झ. घरेलू उद्योग के पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव प्रतिकूल रहे हैं। घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध

30. चूंकि किसी हितबद्ध पक्ष ने उत्तर नहीं दिया है इसलिए इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

31. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। तदनुसार प्राधिकारी द्वारा किए गए क्षति विश्लेषण वस्तुतः घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करते हैं।

मांग का आकलन

32. संबद्ध वस्तु की घरेलू खपत/मांग के आकलन के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ा गया है और उसका सारांश निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	115	124
संबद्ध देश द्वारा आयात	एमटी	231	384	342	216
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	148	94
अन्य देशों द्वारा आयात	एमटी	-	-	-	-
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	123	117

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि की है। इसी प्रकार, क्षति अवधि के दौरान कुल मांग में वृद्धि हुई है।

ज. पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

आयात मात्रा और बाजार हिस्सा

34. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के अनुसार भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के लिए प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आयात आकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
चीन	एमटी	231	384	342	216
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	148	94
अन्य देश	एमटी	-	-	-	-

कुल आयात	एमटी	231	384	342	216
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	148	94
आयातों का बाजार हिस्सा					
संबद्ध देश	%	100.00	100.00	100.00	100.00
अन्य देश	%	-	-	-	-
निम्न के संबंध में आयात					
उत्पादन	%	***	***	***	***
खपत	%	***	***	***	***

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 में बढ़े हैं और उसके बाद उनमें कमी आई है। जांच की अवधि में आयात मूल्य पिछले वर्ष तथा आधार वर्ष (2012-2013) की तुलना में कमी आई है। उत्पादन और खपत के संबंध में आयात में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में भी कमी आई। अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटित आयातों में संपूर्ण दृष्टि से तथा उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि नहीं हुई है

ट. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

36. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में भारी कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों से कीमत में पर्याप्त स्तर तक गिरावट आई है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री और कीमत ह्रास यदि कोई हो, के संबंध में जाँच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पंहुच लागत के साथ की गई है।

कीमत कटौती

37. घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति ज्ञात करते समय, घरेलू उद्योग द्वारा दी गई रिबेट, छूटों और कमीशनों और प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को घटाया गया है। आयातों के पंहुच मूल्य की गणना 1 प्रतिशत पंहुच प्रभार और लागू मूल सीमाशुल्क और संबद्ध देश से सीआईएफ कीमतों के लिए शिक्षा उपकर को जोड़कर की गई है, जैसा प्रत्येक प्रतिवादी निर्यातक ने बताया है। अन्य श्रेणी के लिए, पंहुच कीमत का परिकलन डीजीसीआईएंडएस आकड़ों के अनुसार आकलन योग्य मूल्य में लागू मूल सीमाशुल्क और शिक्षा उपकर को जोड़कर किया गया है।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
आयातों की पंहुच कीमत	रू./एमटी	213.10	228.54	312.69	279.28
सूचीबद्ध		100	107	147	131
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./एमटी	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
सूचीबद्ध		100	106	122	116
कीमत कटौती	रू./एमटी	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25	15-25	(5)-5	0-10

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कटौती 2012-13, 2013-14 और जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक थी परंतु 2014-15 के दौरान नकारात्मक थी। इसके अतिरिक्त कटौती की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान कम हुई है।

पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री प्रभाव

39. पाटित आयातों के कीमत ह्रास और कम कीमत पर बिक्री प्रभावों की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और पीओआई समेत क्षति अवधि के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पंधुच मूल्य के संदर्भ में की गई है।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध आयातों की पंधुच कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	147	131
बिक्री लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	113	112
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	122	116

40. यह नोट किया जाता है कि आयातों की पंधुच कीमत और बिक्री लागत और बिक्री कीमत— दोनों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में बिक्री कीमत में वृद्धि बिक्री लागत से अधिक है। प्राधिकारी को पाटित आयातों का कोई ह्रास अथवा न्यूनीकरण प्रभाव नहीं दिखाई देता।

ठ. घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों की जाँच

उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

41. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोग का ब्योरा निम्नानुसार है :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	122	130
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	115	124
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	123	117

42. घरेलू उद्योग की उत्पादन की स्थापित क्षमता पीओआई समेत क्षति अवधि के दौरान समान रही है। तथापि, उत्पादन, बिक्री और उसके द्वारा क्षमता उपयोग में मांग में वृद्धि के अनुरूप क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच की अवधि में क्षमता उपयोग आधार वर्ष की तुलना में काफी बढ़ा है। जांच की अवधि में घरेलू बिक्री आधार वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत तक बढ़ी है और पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत तक बढ़ी है।

मालसूची :

43. विचाराधीन उत्पाद की मालसूची से संबंधित आकड़े निम्नानुसार हैं :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
आरंभिक	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	93	33
अंतिम	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	33	140
औसत	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	67	87

44. यह नोट किया जाता है कि औसत मालसूची आधार वर्ष और 2013-14 की तुलना में जांच की अवधि में कम हुई है, यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में वह बढ़ी है।

लाभ और नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

45. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू प्रचालनों के संबंध में लाभ और नकद प्रवाह से संबंधित आकड़े निम्नानुसार दर्शाते हैं :

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
बिक्री लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	113	112
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	122	116
निवल लाभ/हानि	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-114	98	-19
निवल लाभ/हानि	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-121	114	-24
पीबीआईटी	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-994	12,525	5,757
नकद लाभ	लाख रू.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-122	169	22
लगाई गई पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
लगाई गई पूंजी पर आय- एनएफए आधार	रेंज	0-(5)	0-(5)	15-25	5-15

46. लाभ/हानि और नकद प्रवाह के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को 2012-13, 2013-14 तथा जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं। और 2014-15 के दौरान उसने लाभ कमाया है। जांच की अवधि में हानियों की मात्रा आधार वर्ष की तुलना में काफी कम हुई है। जहां तक पीबीआईटी, जो 2012-13 और 2013-14 के दौरान नकारात्मक थी, का संबंध है, वह 2014-15 और जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक हो गई। यही स्थिति नकद प्रवाह के संबंध में भी सही है। आय की दर भी उस अवधि में सुधरी है और जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक हो गई। अतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

47. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित आकड़ों निम्नानुसार दर्शाते हैं :

विवरण	यूओएम	2011- 12	2012- 13	2013-14	पीओआई
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	121	129
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	104	104
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	127	147	213

48. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग प्रति कर्मचारी उत्पादकता में उत्पादन के अनुरूप वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और प्रदत्त मजदूरी में भी वृद्धि हुई है। अतः इन मानदंडों पर भी घरेलू उद्योग ने अपनी स्थिति में सुधार किया है।

ड. पाटन की मात्रा

49. उक्त पाटन मार्जिन से संबंधित खंड से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और पीओआई के दौरान न्यूनतम से अधिक है।

वृद्धि

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता और बाजार हिस्से के अनुसार घरेलू उद्योग की वृद्धि पीओआई के दौरान सकारात्मक रही थी।

ड. वास्तविक क्षति पर निष्कर्ष

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी बात के होते हुए भी, क्षति अवधि के दौरान कुछ उतार-चढ़ाव की प्रवृत्तियों, उत्पादन, बिक्री की मात्रा, माल सूची, प्रति व्यक्ति उत्पादकता आदि की दृष्टि से घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में सुधार हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड घरेलू उद्योग को क्षति होना नहीं दर्शाते।

ण. क्षति एवं क्षति मार्जिन की मात्रा

52. चूंकि आर्थिक मानदंडों के अनुसार क्षति विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, अतः क्षति/क्षति मार्जिन की मात्रा का परिकलन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता, जिसके लिए सामान्य रूप से “कम शुल्क नियम” के सिद्धांत के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की मात्रा का परिकलन करना अपेक्षित है।

त. अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

53. पाटनरोधी भारतीय नियमों और करार के तहत सूचीबद्ध अन्य सूचक मापदंडों, इसकी कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा न्यूनीकरण की शर्तों में, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों की क्षति, मात्रा और कीमत पर प्रभाव की मौजूदगी की जांच करते हुए, प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार यह जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या घरेलू उद्योग की क्षति में पाटित आयातों के अतिरिक्त कोई अन्य कारक अंशदान कर सकता है :-

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के अतिरिक्त, अन्य देशों से संबद्ध वस्तु का आयात न के बराबर है।

ख. मांग का संकुचन और खपत की पद्धति में परिवर्तन

55. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में मांग में कोई कमी नहीं आई है। क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के लिए समग्र मांग में सुधार दर्शाया है।

ग. प्रौद्योगिकी में विकास

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति का कारण बन सकते थे।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है और उल्लेखनीय घरेलू उत्पादन और बिक्री के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों के मध्य कोई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसके अलावा एक बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

58. निर्यात निष्पादन पाटन और क्षति का मूल्यांकन करने में बहुत संगत मानदंड नहीं है, अतः घरेलू उद्योग को क्षति की जांच करने के प्रयोजन के लिए घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को अलग-अलग रखा गया है।

59. तथापि, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में सुधार संबद्ध देश से निर्यातकों की तुलना में शामिल करते हुए विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आपूर्ति में उनकी क्षमता दर्शाता है। उपर्युक्त संपूर्ण विश्लेषण यह दर्शाता है कि समग्र रूप से घरेलू उद्योग निरंतर अपने निष्पादन में सुधार करता रहा है। दोनों कंपनियों के लिए लगाई गई पूंजी पर आय बहुत अच्छी है। बहुत कम किए गए मार्जिन की बात करते हुए संबद्ध देश से आयात की मात्रा जांच की अवधि के दौरान काफी कम हुई है। पाटित आयातों से क्षति होना दिखाई नहीं देता।

थ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

60. उपर्युक्त विश्लेषण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो सूचीबद्ध ज्ञात मानदंड और न ही अन्य कारक, जिनका ऊपर विश्लेषण किया गया है, से घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान अथवा जांच की अवधि के बाद के समय में कोई सतत क्षति होना दर्शाते हैं। घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

61. तथापि, समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि क्या संबद्ध सामान भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आने की संभावना है अथवा आ रहे हैं तथा यदि शुल्क हटाया जाता है अथवा उसमें अंतर किया जाता है तो क्या घरेलू

उद्योग को क्षति इन पाटित आयातों के कारण पुनः होने की संभावना है। प्राधिकारी ने भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 (7) की दृष्टि से वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों पर विचार करते हुए पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना की जांच की, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है :-

“वास्तविक क्षति की आषकां का निर्धारण तथ्यों पर आधारित हागे और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और; (क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो। (ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो। (ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा (घ) उस वस्तु की वस्तु सूची की जांच की जा रही हो।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

62. घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के अपने दावे के समर्थन में निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

- क. संबद्ध देश के संबंध में अभिनिश्चितता पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है अपितु मूल रूप से निर्णायक समीक्षा जांच में महत्वपूर्ण भी है। पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, इन निर्यातकों को भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लिए अत्यधिक सुअवसर प्राप्त होंगे और वे घरेलू बाजार का हिस्सा ले जाएंगे। भारतीय उत्पादकों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा कि उन्हें बाजार में बने रहने के लिए भारी क्षति का सामना करना पड़ेगा या अपने संयंत्र बंद करने पड़ेंगे।
- ख. आयातों की मात्रा पाटनरोधी शुल्क को लगाने के बावजूद उल्लेखनीय रूप से ऊंची है जो यह दर्शाती है कि प्रवृत्त वर्तमान शुल्कों की समाप्ति के मामले में आयातों की मात्रा कई गुना वृद्धि होने के लिए इस प्रकार बाध्य है कि वे भारतीय घरेलू उद्योग को बरबाद कर देंगे।
- ग. संबद्ध देश में उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशाल क्षमता अनुरक्षित करते हैं। यह नोट किया जाना चाहिए कि आयात तभी वृद्धि के लिए बाध्य हैं जब संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक ऐसे विशाल अनुपातों की क्षमता धारण करते हैं।
- घ. पूरे विश्व में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री उल्लेखनीय है। यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देश में उत्पादक अपने उत्पादन का महत्वपूर्ण प्रतिशतांक निर्यात करते हैं। शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, इन निर्यातकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत में अपने निर्यातों की वृद्धि करने की संभावना है।
- ङ. कीमतें, जिन पर संबद्ध वस्तुएं आयातित की जा रही हैं, उस कीमत से उल्लेखनीय रूप से कम हैं, जिन पर घरेलू बाजार में वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। इसलिए शुल्क की समाप्ति के मामले में संबद्ध देश से निर्यातक, इसकी उल्लेखनीय क्षमता के आलोक में, भारतीय बाजार में अपने उत्पाद को और अधिक सरणीबद्ध करेंगे।

- च. विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपने स्रोत का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण विचार होने के कारण कीमत के साथ ही करते हैं। ऐसा मामला होने के कारण, संबद्ध देश से किसी पाटनरोधी शुल्क के बिना इतनी कम कीमत के आयातों की उपलब्धता निश्चित रूप से घरेलू बाजार पर उस स्थिति से और अधिक विपरीत प्रभाव डालेगी जो वह इस समय डाल रही है।
- छ. वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देश का बाजार हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। यह दृढ़तापूर्वक सुझाव देता है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में बाजार हिस्सा और अधिक वृद्धि के लिए आबद्ध है।
- ज. यदि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के लिए स्वीकृति दी जाती है तो घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय हानि, नकद हानि और निवेश पर नकारात्मक वापसी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में महत्वपूर्ण क्षति उठाने की संभावना है।
63. इसके अतिरिक्त प्रकटीकरण के बाद की अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी को यह निर्धारित करना है कि पाटनरोधी शुल्क के घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति का कारण बनने की संभावना है। इसलिए, ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, प्राधिकारी द्वारा संभावित विश्लेषण किया जाना है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

64. चूंकि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उत्तर नहीं दिया है, इस संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

65. उपर्युक्त के मद्देनजर नियमावली के अनुबंध-2 की धारा (7) के तहत संभावना के पहलू पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर निम्नलिखित रूप में विचार किया है।

(i) पर्याप्त रूप से बड़े हुए आयात की संभावना दर्शाते हुए भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की पर्याप्त दर

66. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात केवल संबद्ध देश से आ रहे हैं, निम्नलिखित तालिका संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में स्थिति दर्शाती है :-

	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई	2016-17
आयात मात्रा	मी.ट.	231	384	342	216	192
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	166	148	94	83
पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन	%	-	66.23	-10.94	-36.84	-10.98

67. यह नोट किया जाता है कि आयात मात्रा में जांच की अवधि के दौरान निरंतर घटती प्रवृत्ति रही है। जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी यह प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है। अतः इस स्तर पर भारत में पाटित आयातों में काफी वृद्धि अथवा अंतर्निहित वृद्धि का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

(ii) किन्हीं अतिरिक्त निर्यातकों को खपाने में अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पर्याप्त रूप से बड़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना को दर्शाने वाले निर्यातकों की क्षमता में काफी स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, अथवा आसन्न, पर्याप्त वृद्धि

68. संस्थापित क्षमता और अथवा पर्याप्त रूप से असहमत स्तर पर वैश्विक व्यापार आंकड़ों के संबंध में स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया। इसलिए, केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर आधारित यह निष्कर्ष नहीं लगाया जा सकता कि निर्यातकों के पास पर्याप्त स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल आविष्कार हैं, या क्षमता में एक आसन्न संस्थापक वृद्धि को निष्पादित करने से भारत में पर्याप्त मात्रा में बड़े हुए निर्यात को कम होने की संभावना का संकेत मिलता है।

(iii) क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर ह्रासमान अथवा दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और जिनसे और अधिक आयात के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी; और

69. डीजीसीआईएस से प्राप्त आंकड़ों सहित घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार ह्रासमान/न्यूनीकरण की संभावित कीमत का जांच की अवधि के बाद का विश्लेषण क्षति की अवधि के दौरान दर्शित प्रवृत्ति जारी रहना दर्शाता है। यद्यपि, जांच की अवधि के बाद पहुंच मूल्य जांच की अवधि के दौरान के पहुंच मूल्य की तुलना में कम हो रहा है तथापि, बिक्री कीमत बढ़ रही है जबकि बिक्री की लागत कम हो रही है। यह आयात का कीमत ह्रासमान अथवा न्यूनीकरण की मौजूदगी न होने का प्रमाण है।

विवरण	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	213	229	313	279
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	147	131
बिक्री लागत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	113	112
बिक्री कीमत	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	122	116

(iv) संबद्ध देश में जांच की जा रही वस्तु की मालसूची

70. चीन जन.गण. में निर्यातकों के पास स्टॉक के संबंध में पर्याप्त/निर्भर योग्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

71. पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंडों में सुधार हुआ है। उत्पादन, क्षमता उपयोग, मांग और बिक्री सभी में सुधार हुआ है। यह वित्तीय परिणामों में भी सामने आया है, जहां घरेलू उद्योग नकद लाभ दर्शा रहा है। जांच की अवधि में अधिक क्षति गैर-प्रचालनात्मक कारणों से हो सकती है। भारत में पाटन पुनः शुरू करने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों की संभावना के विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि इस पर

विश्वास करने का कोई अंतर्निहित कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के सुधरे हुए निष्पादन को देखते हुए यह एक स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग को कोई क्षति होगी।

द. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

72. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां केवल घरेलू उद्योग से प्राप्त हुई हैं। किसी भी निर्यातक अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार ने प्रकटन पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

73. घरेलू उद्योग ने अपनी टिप्पणियों में यह दोहराया है कि घरेलू उद्योग भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता तथा क्रेताओं की कीमत संवेदनशीलता के कारण सुभेद्य रहा है। उन्होंने जोर दिया कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो पाटन के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना बहुत अधिक है। उन्होंने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद निरंतर क्षति हो रही है और उन्होंने यह प्रार्थना की है कि अम.डॉ./कि.ग्रा. में व्यक्त शुल्क को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया जाए।

74. डीआई द्वारा पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियों में कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है। प्राधिकरण ने टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और इन अंतिम निष्कर्षों में प्रासंगिक स्थानों पर उन्हें संबोधित किया है।

घ. निष्कर्ष

75. उठाए गए विवादों, प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, जैसाकि इस जांच परिणाम में दर्ज किया गया है और पाटन एवं परिणामी क्षति के जारी रहने की स्थिति के उपर्युक्त विश्लेषण व पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संबद्ध देश अर्थात् चीन जन.गण. से संबंधित उत्पाद के आयात में काफी कमी आई है। ये आयात संपूर्ण दृष्टि से भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में दोनों दृष्टि से कम हुए हैं। चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात तथा जिस कीमत पर उसका आयात किया जा रहा है, उससे क्षति होने की संभावना नहीं है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद हो जाता है, विशेष रूप से जैसा कि यह देखा गया है, प्रमाणित रूप से कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं है।

76. इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्षति सर्वोत्तम सामान्य है और वह पाटन आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण हो सकती है। उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग का निष्पादन इस जांच के लिए विचार में लाए गए 4 वर्षों की क्षति अवधि में सुधरा है। इस निमित्त किए गए संभावना के विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने की संभावना नहीं है।

न. सिफारिशें

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी और सभी संबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सतत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलु पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। घरेलू उद्योग के अलावा, किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, सतत पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में वर्तमान समीक्षा जांच की शुरुआत तथा जांच किए जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से निर्यातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त, शुल्क समाप्त किए जाने के मद्देनजर क्षति की संभावना का विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने का कोई कारण नहीं

है। उपर्युक्त निष्कर्ष निकाले जाने पर प्राधिकारी का यह मत है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।

78. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के विरुद्ध इस सिफारिश से उत्पन्न कोई अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखी जाएगी।

(डा. इन्द्रजीत सिंह)

अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th of August, 2017

FINAL FINDINGS

Subject: Sunset Review (SSR) Anti-dumping investigation concerning imports of ‘1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone’ originating in or exported from China PR.

No. 15/3/2016—DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), had issued final findings *vide* Notification No.14/11/2004-DGAD dated 16th November, 2011, recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of “1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone” (hereinafter referred to as the subject goods, or product under consideration or Pyrazolone), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country). The definitive anti- dumping duties were accordingly imposed by the Central Government *vide* Notification No. 01/2006- Customs (ADD) dated 10th January, 2006.
2. And whereas, the Authority, in pursuance of the initiation of the Sunset review *vide* notification F.No.15/5/2010-DGAD dated 1st July, 2010 had issued final findings *vide* Notification No.15/5/2010-DGAD dated 29th June, 2011, recommending the extension of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country. The definitive anti- dumping duties were accordingly extended by the Central Government *vide* Notification No. 80/2011- Customs (ADD) dated 24th August, 2011.
3. Whereas, M/s Prima Chemicals and M/s Polygon Chemicals, (hereinafter referred to as the “petitioner companies’ or “the applicants”), have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, contending likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the existing anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

4. Whereas in view of duly substantiated application filed and in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation *vide* Notification No. Notification No. 15/3/2016-DGAD dated 11th August, 2016 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
5. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government has extended the existing anti-dumping duty levied on subject goods up to 23rd August 2017 *vide* notification No.47/2016-Customs (ADD) dated 19th August 2016, against imports from China PR.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - a. The Authority sent copy of the initiation notification dated 11th August, 2016 to the embassies of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per available information. The known interested parties were requested to file the questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - b. Copy of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
 - c. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the applicant was sent to the known exporters and the embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - d. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the SSR to the following known producers/exporters in the subject country and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4) of the Rules:

M/s Goldlink Industries Co, Ltd.,
17/F,258, Zhong Shan Road, Wuxi, China

M/s Jiangsu Changyu Chemical Co., Ltd.
Zhongzhichang Leyu Town Zhangjiag City
Jiangsu, 215621, P. R. China.

M/s Qingdao Bangli Fine Chemical Co., Ltd
No 608 Yanshan Road Oingdao City, China

M/s Qingdao Double-Peach Specialty Chemicals (Group) Co., Ltd
Block C, 43, Zhengzhou Road, Qingdao China

M/s Wenzhou Meiernuo Chemical Co. Ltd.

Contact: Zhejiang Wenzhou Ohai Xinqiao Street Ningbo Road' Zip Code:
325000, China

M/s Jinan Xiangrui Chemical Co. Ltd.

No.12406, Jingshi Road, Jinan, Shandong, China

M/s Shandong Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd.

Zibo, Shandong. China

M/s Shouguang Nuomeng Chemical Co. Ltd.

Houzhen Industrial Park, Shouguang, Shandong, China

- e. In response to the initiation of the subject investigation, none of the producers/exporters from the subject country responded by filing questionnaire response and no submissions were made.
- f. Questionnaire was sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules:

M/s Apex Dyes & Intermediates

Off Ajanta Comm'l. Centre

Ashram Road, Ahmedabad 380014

M/s AS Associated Drug Co.

27 Bull Temple Road, Bangalore

M/s Pidilite Industries Ltd.

Ramkrishna Mandir Road

Off M.Vasanji Road

Andheri East, Bombay 400059

M/s Asiatic Colours Chem Ind. Ltd.

Plot No. I503, 04 G, I. D. C. Estate

Phase-I, Naroda, Ahmedabad

M/s Ankur Dyestuff Industries

39, G. L. D. C, Phase LI,

Vatva, Ahmedabad

M/s Jansons International
101, Jolly Bhavan No,1,
10, New Marine Lines, Mumbai-400 200

M/s K, Rasiklal & Co.,
R. No. 5, Lind Floor, 339/340, Samuel Street
Masjid, Mumbai.3

M/s Nilkantha Chemicals,
Plot No. 8021, GIDC Estate, Sachine, Surat

- g. In response to the above notification, no importers/users filed importer questionnaire response and no submissions were made.
- h. Exporters, foreign producers and other interested parties have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, and hence they have been treated as non-cooperating interested parties.
- i. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange for details of imports of subject goods for the past three years in addition to the period of investigation. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis.
- j. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-Dumping Rules.
- k. Investigation was carried out for the period starting from April 2015 to March 2016 (POI). However, injury examination was conducted for the periods, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14- Mar'15 and the Period of Investigation.
- l. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 10th July, 2017. Only the domestic industry attended the oral hearing and filed written submissions of the views expressed orally.
- m. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- n. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded the Final Findings on the basis of available facts.

- o. In accordance with the Rules the Authority issued a disclosure statement containing all essential facts of the case on 22nd July 2017 for the comments of the interested parties. Only the domestic industry filed comments on disclosure statement. The comments, to the extent they were relevant, have been addressed in this finding in appropriate places.
- p. ‘***’ represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- q. The average exchange rate of 1US\$ = Rs. 65.91 prevailing during the POI has been adopted by the Authority

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

Submissions made by the Domestic Industry

- 7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article:
 - a. The product under consideration in the present petition is “1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone” also referred to as Pyrazolone.
 - b. Since present investigation is for a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation and previous sunset review.
 - c. There is no difference in Pyrazolone produced by the Indian industry and the product exported from the subject country. Pyrazolone produced by the Indian industry and imported from the subject country is comparable in essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably.
 - d. Pyrazolone produced by the domestic industry should be treated as like article to the Pyrazolone imported from the subject country in accordance with the Anti-Dumping Rules.

Submissions by other interested parties

- 8. No submissions have been made by other interested parties with regard to product under consideration.

Examination by the Authority

- 9. The Product under Consideration (PUC) in the original investigation, the previous sunset review as well as in the present review is ‘1-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone’. In the original investigation as well as the previous sunset review investigation, the product was defined as under:

“10. The Authority notes that since present investigation is a sunset review investigation, the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. The product under consideration in the previous as well as present investigations is Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone, an organic chemical, classified under Chapter 29 under Sub-heading 29 33 19 20. Product under consideration is used in dye and pharmaceutical industry for manufacture of Analgin, Solvent Dyes and Pigment Dyes, and Pigment orange 13. The imports of subject goods are also reported under customs classification No. 293319, 291634, 291739, 292429, 293311, 293359, 294200, 980200 as well. However, the Customs classifications are indicative only and not binding on the Authority. The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product. There is no known difference in product under consideration produced Examination by the Authority. 6 by the Indian industry and subject goods exported from subject countries. Moreover, due to

absence of any response from the producers/exporters of the subject goods from the subject country there is no view contrary to the view held by the domestic industry and the Authority. The Authority therefore proposes to hold that the two are like article as per Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.”

10. The present investigation being a sun set review investigation and antidumping duty as earlier recommended by the Authority being in force on the imports of the subject goods from the subject country, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the original and the mid-term review investigations. Moreover, none of the interested parties have made any submission requesting modification (including curtailment) in the scope of the review.
11. The domestic industry has claimed that the subject goods produced by the domestic industry are identical to the product under consideration being imported into India. The domestic industry has also claimed that there is no known difference in domestic industry's product and product under consideration exported from the subject country and the two are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from the subject country and both are technically and commercially substitutable.
12. The Authority notes from the information available on record that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. It is further noted that the Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the previous investigation, which is relied upon. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are held as “like article” in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably and are like article within the meaning and scope of Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the domestic industry

13. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
 - a. M/s. Vani Pharma Labs and M/s Kolorjet Chemicals Pvt. Ltd. are, apart from the applicants, are the only other known producers of the product under consideration as per information available on their website.
 - b. The production details of these producers are not available. In any case, the production of the applicants will easily be more than 50% of the total Indian Production.
 - c. The petitioners are not related to the exporters/producers or importer of the product under consideration nor have they imported the product under consideration.

Submissions made by other interested parties

14. No submissions have been made by other interested parties with regard to standing of the domestic industry.

Examination by the Authority

15. The Authority notes that M/s Prima Chemicals and M/s Polygon Chemicals had filed application for seeking continuation of anti-dumping duties. In the final findings of the original investigation and the previous sunset review investigation, the Authority had considered M/s Prima Chemicals and M/s Polygon Chemicals as “domestic industry”, in accordance the requirements of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules. Petitioners have submitted that M/s. Vani Pharma Labs and M/s Kolorjet Chemicals Pvt. Ltd have claimed to produce subject goods on their websites but have not responded in this or the earlier investigations. As per

information on record, production of the petitioner companies constituted *** of Indian production during the POI. Having regard to previous investigation on subject goods and the information as available with the Authority, it is considered that M/s Prima Chemicals and M/s Polygon Chemicals in any case constitute “a major proportion” of total Indian production. Further the petitioners have not imported the subject goods nor are they related to either the importers or exporters thereof.

16. It has been brought to the notice of the Authority that since 1st April 2016 Polygon Chemicals has been merged with Prima Chemicals. However, it is noted that since the development is post period of investigation and further since this is merger of one of the applicant company into other company, the applicants are treated as separate but related entities for the purpose of present investigation.
17. In view of the above position and having regard to the Rules and information on record, the Authority holds that M/s Prima Chemicals and M/s Polygon Chemicals, constitute domestic industry for the purpose of the present review investigations.

E. DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Submissions made by the Domestic industry

18. The submissions made by the domestic industry with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin are as follows:
 - a. Article 15(b) of China’s Accession Protocol implies that provisions of Clause 15(a)(ii) shall expire 15 years from date of China’s Accession, i.e., provisions of this paragraph shall be available for 15 years, i.e., upto Dec., 2016. This implies that Authority will have to consider the costs and process for determination of normal value.
 - b. Relevant consideration in this regard must be the investigation period as the purpose of fixation of investigation period is to consider a period when the existence of dumping causing injury is established and that the developments occurring after the POI are not relevant for the determination.
 - c. Since the POI in the present case is April, 2015 – March, 2016 (12 Months), the provisions of Article 15 shall be fully applicable to the present investigation period. The normal value in China should be determined on the basis of Para-7 of Annexure-I. The petitioner requests the authority to kindly determine normal value in China in accordance with Para 7 & 8 of the Rules. For determination of normal value in China on the basis of Para 7 and 8, petitioner requests the authority to kindly consider the detailed submissions enclosed with the petition filed earlier.
 - d. Normal Value in China has been determined on the basis of cost of production in India, duly adjusted with selling, general and administrative expenses and considering the consumption norms of the petitioners.
 - e. The petitioners have relied upon import data provided by IBIS. The values reported in import data are CIF values. The export prices being CIF value while the normal values being at ex-factory level, the export prices have been adjusted for expenses on Ocean Freight, Marine insurance, Commission, Inland Freight, Port expenses and Bank charges
 - f. Considering the normal value and export price as discussed, the petitioners have determined dumping margins, details of which can be seen from the petition on record. The dumping margins from the subject country are not only above de minimis levels, but continue to be substantial despite imposition of antidumping duty.

Submissions made by other interested parties

19. Since no interested parties have responded, no submissions have been made with regard to Market Economy Claims, Normal Value, Export Price and Dumping Margin

Normal value in China PR

20. Article 15 of China’s Accession Protocol provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - i. If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - ii. The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a) (ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector?”*

21. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is April, 2015 to March, 2016. Since the subparagraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
22. The Authority notes that in the past three years, China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.

Examination of Market Economy Claims by the Authority:

23. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters in the subject country for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested embassy of subject country in India to advise the producers/exporters in their country to provide the required information. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and establish to the contrary. However, none of the producers/exporters in the subject country have cooperated and filed response to the exporter's questionnaire and MET questionnaire in the present investigation. In view of this position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption, the Authority considers it appropriate to proceed with Para-7 of Annexure-I to the Rules for determination of Normal Value for China PR.

F. DETERMINATION OF NORMAL VALUE

24. None of the exporters/producers from the subject country have cooperated with the Authority and responded to the present investigation. Further none of the interested parties have provided any other alternate basis as defined in the Rules on which normal value can be determined.
25. In view of the above position and considering China as a non market economy, the Authority has determined the normal value in accordance with para 7 of Annexure I of the AD Rules. In absence of sufficient information on record regarding the other methods as are enshrined in para 7 of Annexure I of AD Rules, the Authority has determined the normal value by adopting the method "other reasonable basis". The Authority has therefore constructed the normal value for China PR by adopting international prices of key raw materials and best consumption norms of raw material. The other elements of cost are based on the optimised cost of most efficient domestic producer. A profit margin of 5% on constructed cost of sales less finance cost is allowed. Accordingly, the constructed normal value for exporters from China PR is determined as **US\$ 3.83 per Kg** as per Rule 6(8) of Rules.

G. EXPORT PRICE

26. The Authority notes that none of the exporters/producers of subject goods from the subject country have responded to the Authority in the form and manner prescribed. In the absence of exporter's questionnaire response from the producers/exporters from the aforesaid countries, the Authority has determined the export price in respect of these countries on the basis of best available information in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has relied upon DGCI&S import data for the purpose of arriving at the weighted average CIF value of imports from the aforesaid countries during the POI. Adjustments on account of ocean freight, insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges, as per the best available information in terms of Rule 6(8), have been considered to arrive at the net export price in respect of the said countries. Accordingly, export price at ex-factory level for all exporters of China PR is determined as given in the dumping margin table given below.

H. DUMPING MARGIN

27. Comparing the aforesaid normal value and export price as determined, the dumping margin as determined for the subject country during POI is as follows:

POI (2015-16)

Country	Exporter/ Producer	Constructed Normal Value US\$/Kg	Net Export Price,US\$/Kg	Dumping Margin,US\$/ Kg	Dumping Margin %	Dumping Margin % Range
China PR	Any	3.83	***	***	***	***

28. The above table shows that dumping has continued despite anti-dumping duties in force during the injury period.

I. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the Domestic Industry

29. Following are the submissions made by the Domestic industry in this regard:

- a. Despite anti-dumping duties in force the subject imports have still been undercutting the domestic industry and that too by a significant margin which clearly shows the probability of this to increase further in case there is cessation of the present anti dumping duties.
- b. Comparison of cost of production and selling price shows that, both, cost of sales and selling price of the domestic industry declined throughout the injury period. However, decline in selling price is much more than the decline in cost of sales. It is thus evident that the imports are depressing the prices of the domestic industry in the domestic market.
- c. The capacity with domestic industry is comparable to Indian demand. Thus, the domestic industry could have easily utilized its capacities and imports are not necessary in the domestic market.
- d. The production and sales of the domestic industry increased throughout the injury period. The production and sales of the domestic industry increased as a natural consequence of antidumping duties imposed during that period. Capacity utilization of the domestic industry has also increased. However, the same is much below the achievable levels.
- e. Inventories with the Domestic Industry have declined over the injury period.
- f. Profits, profit before interest and cash profits, all have remained adverse throughout the injury period. In spite of increase in production and sales, domestic industry suffered financial losses. Losses have declined, however remains substantial. The return on capital employed has seen a marginal improvement over the injury period.
- g. Demand of subject goods has increased over the injury period. Subject imports hold significant market share despite domestic industry having sufficient capacity to cater the domestic demand.
- h. Productivity has increased over the injury period in view of increase in production. In spite of this increase, domestic industry still had to bear financial losses because of dumping of the product under consideration in the Country.
- i. The consequent impact of the dumped imports on the domestic industry has been adverse. The domestic industry has suffered injury.

Submissions made by other Interested Parties

30. Since none of the interested parties have responded no submissions in this regard have been received.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

31. The Authority has taken note of the submissions made by the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the Domestic industry.

Assessment of Demand

32. For the purpose of assessment of the domestic consumption/ demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same has

been summarized below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>115</i>	<i>124</i>
Imports by Subject Country	MT	231	384	342	216
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>166</i>	<i>148</i>	<i>94</i>
Imports by Other Country	MT	-	-	-	-
Total demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>123</i>	<i>117</i>

33. The Authority notes that sales of the domestic industry have consistently grown during the injury period. Similarly, the total demand has increased over the injury period.

J. VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

Import Volume and Market Share

34. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analysed as under:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
China	MT	231	384	342	216
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>166</i>	<i>148</i>	<i>94</i>
Other Countries	MT	-	-	-	-
Total Imports	MT	231	384	342	216
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>166</i>	<i>148</i>	<i>94</i>
Market Share in Imports					
Subject country	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Other Countries	%	-	-	-	-
Imports in relation to					
Production	%	***	***	***	***
Consumption	%	***	***	***	***

35. The Authority notes that import from the subject country increased in 2013-14 as compared to previous year and has declined thereafter. Import Value declined in POI as compared to previous year as well as base year (2012-2013). Imports in relation to production and consumption has also declined during the POI, as compared to base year as well as the previous year. Hence, the Authority finds that there has not been significant increase in dumped imports, both in absolute terms as well as in relation to production and consumption.

K. PRICE EFFECT OF THE DUMPED IMPORTS ON THE DOMESTIC INDUSTRY

36. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the Net Sales Realisation (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

Price Undercutting

37. While working out the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted. The landed value of imports has been calculated by adding 1% landing charge; the applicable basic customs duty and education cess to the CIF prices from the subject country as obtained from the DGCIS data.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Landed price of imports	Rs./MT	213.10	228.54	312.69	279.28
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>107</i>	<i>147</i>	<i>131</i>
Net Sales Realisation	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>		<i>100</i>	<i>106</i>	<i>122</i>	<i>116</i>
Price Undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	15-25	15-25	(5)-5	0-10

38. The Authority notes that undercutting was positive during 2012-13, 2013-14 and POI, but was negative during 2014-15. Further, the extent of undercutting has come down during the POI as compared to the base year.

Price suppression and depression effects of the dumped imports:

39. The price suppression and price depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values of the subject goods from the subject country in relation to injury period including POI.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Landed price of Subject Imports	Rs./kg	213.10	228.54	312.69	279.28
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>147</i>	<i>131</i>
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>113</i>	<i>112</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>122</i>	<i>116</i>

40. It is noted that the landed price of imports and both - cost of sales and selling price - have increased over the injury period. It is also noted that the increase in the selling price is more than the cost of sales over the base year. The Authority does not find any price suppressing or depressing impact of dumped imports.

L. EXAMINATION OF OTHER ECONOMIC PARAMETERS OF DOMESTIC INDUSTRY
Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

41. The Production, Capacity and Capacity Utilization details of PUC are as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Production	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>122</i>	<i>130</i>
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>115</i>	<i>124</i>
Demand	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>123</i>	<i>117</i>

42. The installed capacity of production of the domestic industry has remained same during the injury period including the POI. However, production, sales and thereby the capacity utilization have increased over the injury period in line with increase in demand. Capacity utilization in POI has increased substantially as compared to base year. Domestic sales in POI have increased by 24% as compared to base year and up to 7% as compared to previous year.

Inventories

43. Data relating to inventories of PUC shows as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Opening	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>33</i>
Closing	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>93</i>	<i>33</i>	<i>140</i>
Average	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>87</i>

44. It is noted that average inventories have decreased in POI as compared to base year and 2013-14, although it increased as compared to previous year.

Profits and actual and potential effects on the cash flow

45. The data relating to profits and cash flow with respect to the domestic operations of the PUC show as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>113</i>	<i>112</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>122</i>	<i>116</i>
Net Profit/ Loss	Rs./Kg	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-114</i>	<i>98</i>	<i>-19</i>
Net Profit/ Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-121</i>	<i>114</i>	<i>-24</i>
PBIT	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-994</i>	<i>12,525</i>	<i>5,757</i>
Cash Profit	Rs.Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>-100</i>	<i>-122</i>	<i>169</i>	<i>22</i>
Return on Capital Employed – NFA Basis	%	***	***	***	***
Return on Capital Employed – NFA Basis	Range	0-(5)	0-(5)	15-25	5-15

46. With regard to Profit/ Loss and cash flow, it is noted that the domestic industry has incurred losses during 2012-13, 2013-14 and POI, and earned profit during 2014-15. The quantum of losses in POI decreased substantially as compared to base year. As regards PBIT which was negative during 2012-13 and 2013-14, it turned positive during 2014-15 and POI. Same holds true about cash profits. Rate of return also improved during that period, and became positive during POI. Hence, the Authority finds that the overall financial health of DI has improved.

Employment, Wages and Productivity

47. The data relating to employment, wages and productivity show as follows:

Particulars	UOM	2011- 12	2012- 13	2013-14	POI
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>121</i>	<i>129</i>
Employment	Nos	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>104</i>
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>127</i>	<i>147</i>	<i>213</i>

48. It is noted that productivity per employee of the domestic industry has increased in consonance with the movement of production. There was marginal increase in the number of employees over the injury period and the wages paid have also increased. Hence, on these parameters also the DI has improved its position.

M. MAGNITUDE OF DUMPING

49. It is observed from the section pertaining to Dumping Margin above that dumping margin in respect of the imports of the subject goods from the subject country is positive and above *de minimis* during the POI.

Growth

50. The Authority notes that the growth of the domestic industry in terms of production, sales, profitability and market share was positive during POI.

N. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY

51. The Authority notes that notwithstanding, some fluctuating trends during injury period, overall performance of the domestic industry has improved in terms of production, sales volumes, inventory, productivity per employee etc. Thus, the Authority notes that the economic parameters of the domestic industry do not show existence of injury to DI.

O. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

52. As the injury analysis as per economic parameters have shown that injury to DI does not exist, it does not appear necessary to calculate the magnitude of injury/ injury margin, which is generally required for calculating the quantum of anti-dumping duties in accordance with “Lesser duty Rule” principle.

P. OTHER KNOWN FACTORS & CAUSAL LINK

53. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping, the Authority is required to examine whether any factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:

a. Volume and prices of imports from third countries:

54. The Authority notes that during POI, imports of the subject goods from countries other than the subject country have remained non-existent.

b. Contraction of demand and changes in the pattern of consumption:

55. The Authority notes that there is no contraction in the demand over the injury period. Overall demand for subject goods has shown improvement over the injury period.

c. Developments in technology:

56. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

57. The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the major producer of the subject goods and account for significant domestic production and sales. Further there is no perceptible competition among the domestic producers, except that is obvious of a market economy.

e. Export performance of the domestic industry:

58. Export performance is not a very relevant parameter in assessing dumping or injury, therefore, the price and profitability in the domestic and export market have been segregated for the purpose of examining injury to the

domestic industry. However, the improving export performance of the domestic industry does exhibit their ability to competitively supply to the world market including against the exporters from the subject country.

59. The entire analysis above shows that the domestic industry, on the whole, has been steadily improving its performance. The return on capital employed for both the companies is very healthy. The volume of imports from the subject country while coming at what is a much reduced margin, has decreased significantly during the POI. Dumped imports does not appear to have caused injury to DI. It is well possible that the injury to DI, even if there to some extent, could be due to internal reasons and/ or factors other than dumped imports rather than dumped imports.

Q. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

60. From the above analysis, the Authority notes that neither the listed known parameters nor the other factors analysed above show any continued injury to the domestic industry either during POI. The economic health of the domestic industry has improved.
61. However, in a review investigation, the Authority has to determine as to whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to recur due to these dumped imports if the duty is removed or varied. The Authority examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure II (vii) of the Indian Anti-Dumping Rules, which states as under:

“A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances, which would create a situation in which the dumping would cause injury, must be clearly foreseen and imminent. In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the Designated Authority shall consider, inter alia, such factors as;

- a. a significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.*
- b. Sufficient freely disposable or an imminent, substantial increase in capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely to increase demand for further imports and,*
- d. Inventories of the article being investigated.”*

Submissions by the domestic industry

62. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury
- a. The dumping margins ascertained with respect to the subject country were not only above *de minimus* but also substantial in the original as well as sunset review investigation. In the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters will get a greater opportunity to dump the product under consideration into India, taking away the market share of the domestic industry. The Indian producers would be left with no options but to suffer heavy losses to sustain in the market or to close their plants
 - b. Volume of imports has been significantly high despite imposition of anti dumping duty which, in turn indicates that in case of cessation of the present duties in force, the import volumes are bound to increase multiple folds such that they will decimate the Indian domestic country
 - c. Producers in the subject country maintain enormous capacities to produce the subject goods. It is to be noted that the imports are bound to increase when the producers of the subject goods in the subject country possess capacities of such mammoth proportions.
 - d. The export sales of the product under consideration from the subject country around the globe are significant. It would be seen that the producers in the subject country export significant percentage of their production. In the event of cessation of duty, these exporters are likely to increase their exports to India at

dumped prices.

- e. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters from subject country would further channelize their output in the Indian market in view of the significant capacity with it.
 - f. The Indian market for the product under consideration is highly price sensitive. The consumers decide their source, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low priced imports without any dumping duties from subject country in the market would definitely cause a further adverse impact over the Domestic Industry from what is being made presently.
 - g. The market share of subject country is quite significant in spite of the existing anti dumping duties. This strongly suggests that the market share is bound to increase further in the event of cessation of the current duties.
 - h. The domestic industry would suffer huge financial losses, cash losses and negative return on investment if the anti dumping duty is allowed to cease. Hence, the domestic industry is likely to suffer material injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
63. In addition, the domestic industry has, in its post disclosure comments, submitted that the Authority has to determine that anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Therefore, in order to come to such a conclusion, the Authority has to undertake a likelihood analysis.

Submissions made by other interested parties

64. Since none of the interested parties have responded, no submissions have been made in this regard.

Examination by the Authority

65. In view of the above, while considering the likelihood aspect under clause (vii) of Annexure II to the Rules the Authority, *inter alia*, considered the following factors:

(i) A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;

66. The Authority notes that the imports are coming mostly from the subject country, the table below shows the situation regarding import of the subject goods from the subject country:

	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI	Post POI
Import Vol.	MT	231	384	342	216	192
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>166</i>	<i>148</i>	<i>94</i>	<i>83</i>
Change over Previous Year	%	-	66.23	-10.94	-36.84	-10.98

67. The import volumes it may be noted is on a steady decreasing trend during the POI. Even in the post-POI period the decreasing trend is continuing. Therefore, there is no direct evidence of an inherent or significant increase in dumped imports into India, at this stage.

(ii) Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

68. The precise data regarding the installed capacity and or global trade figures at a sufficiently disaggregated level is not available. DI has not submitted any evidence in this regard. Hence, merely based on the submission by the DI, it cannot be concluded that exporters have sufficient freely disposable inventories, or executing an imminent substantial increase in capacity indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to India.

(iii) Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

69. The post-POI analysis of the possible price suppression and depression in accordance with the data provided by the domestic industry along with data obtained from the DGCIS below shows continuation of the trend seen during the injury period. While the landed value has reduced somewhat in post-POI as compared to POI, the selling price has increased while the cost of sales is decreasing. This evidences the absence of any price suppressive or depressive impact of the imports.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI	Post POI
Landed price of Subject Imports	Rs./kg	213	229	313	279	265
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>147</i>	<i>131</i>	<i>124</i>
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>107</i>	<i>113</i>	<i>112</i>	<i>104</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>122</i>	<i>116</i>	<i>119</i>

(iv) Inventories of the article being investigated in the subject country:

70. Adequate/ dependable data is not available about the stock in hand with the exporters in China PR. DI has not submitted any reliable evidence in this regard.
71. It may be noted from the preceding analysis; the performance parameters of the domestic industry have improved during the period of investigation. Production, capacity utilisation, demand and sales have all improved. This is reflected in the financial results as well, where the domestic industry is showing cash profits. The overall loss in the period of investigation could therefore be attributable to factors other than dumped imports. The likelihood analysis of the possibility of the subject country exporters recommencing dumping into India shows that there is no inherent reason or cause to believe so. Further, given the improved performance of the domestic industry, the imports not likely to cause any injury to the domestic industry.

R. POST DISCLOSURE COMMENTS

72. Post Disclosure comments have been received only from the domestic industry. None of the exporters or any interested parties have commented on the disclosure.

Submission by the domestic industry

73. The domestic industry in its comments has reiterated that the domestic industry remains vulnerable due to the price attractiveness of the Indian market and the price sensitive buyers here. They stressed that the likelihood of continuation or recurrence of dumping is very high in case the current anti-dumping duty is terminated. They have stated that the DI suffers continued injury in spite of existing anti-dumping duties and prayed that a duty expressed in US\$/Kg be imposed for a further period of 5 years.

Examination by the Authority

74. No new facts have been brought out by the DI in the post disclosure comments. The Authority has noted the comments and suitably addressed them at the relevant places in these final findings.

S. CONCLUSIONS

75. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that there is a significant reduction in the imports of the concerned product from the subject country i.e., China PR. The imports have reduced both in absolute terms and in relation to production/ consumption in India. Import of the product under consideration from China PR and the price at which it is being imported is unlikely to be injurious should the current anti-dumping duty cease, particularly as it is seen that there is no evidence of any price suppression or depression.
76. Thus, it is concluded that injury is at best nominal and could be due to factors other than dumped imports. The available evidence clearly depict that the performance of the domestic industry has improved over the injury period of four years taken into consideration for this investigation. The likelihood analysis undertaken reveals that the injury is not likely to continue in the event of cessation of the anti-dumping duty.

T. RECOMMENDATIONS

77. The Authority notes that the sunset review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of continued dumping, injury and causal link. No response was received from any interested party other than the domestic industry. Having initiated and conducted the present review investigation into continued dumping, injury and causal link in terms of the Antidumping Rules, the Authority is of the view that the exports from the subject country are not causing material injury to the domestic industry. Further, the analysis of likelihood of injury in view of cessation of duties demonstrates that there is no reason for continuation of anti-dumping duties against the subject goods from the subject country. Having concluded as above, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty, on the imports of the subject goods, originating in or exported from the China PR, is not required.
78. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority